प्रेस विज्ञप्ति

09.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने ऑपरेशन मोबिलाइजेशन (ओएम इंडिया) चैरिटी समूह द्वारा संचालित गुड शेफर्ड स्कूलों के छात्रों से वसूले गए शिक्षण शुल्क और अन्य सहायक शुल्कों के बड़े पैमाने पर गबन, साथ ही सरकारी वित्त पोषित आरटीई और छात्रवृत्ति राशि के गबन की जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 3.58 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपये है।

ईडी ने तेलंगाना की ईओडब्ल्यू (सीआईडी) द्वारा ओएम इंडिया संस्थाओं और उसके प्रमुख पदाधिकारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। सीआईडी ने ऑपरेशन मर्सी इंडिया फाउंडेशन (ओएमआईएफ) और संबद्ध संगठनों के भीतर एक व्यापक संगठित धोखाधड़ी का खुलासा किया, जिसमें विदेशी और घरेलू दान से प्राप्त लगभग 296.6 करोड़ रुपये का गबन और हेराफेरी शामिल है। सीआईडी द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, डॉ. जोसेफ डिसूजा, उनके बेटे जोश लॉरेंस डिसूजा और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों ने दलित फ्रीडम नेटवर्क (डीएफएन) यूएसए, कनाडा और यूके जैसे प्रमुख ईसाई चैरिटी नेटवर्क सहित दानदाताओं से प्राप्त धन को व्यवस्थित रूप से हेराफेरी किया, जो स्पष्ट रूप से दलित और हाशिए पर रहने वाले बच्चों की शिक्षा और उत्थान के लिए था। हालांकि समूह ने मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, सामुदायिक विकास और पुनर्वास सहायता प्रदान करने का दावा किया था, लेकिन सीआईडी ने पाया कि बड़ी मात्रा में धनराशि निजी खातों, सावधि जमा और अचल संपत्ति के लेन-देन में लगाई गई थी। फोरेंसिक ऑडिट से यह भी पता चला कि विदेशी दानदाताओं को छात्र शिक्षा प्रायोजन के लिए प्रस्तुत छात्र डेटा में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया था, जबकि सभी छात्रों से नियमित ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क वसूले गए थे और उन्हें गलत तरीके से "स्थानीय दान" के रूप में दर्ज किया गया था।

ईडी की जाँच से पता चला कि ओएमआईएफ़ को दलित और समाज के अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों के छात्रों की शिक्षा और स्कूलों के निर्माण व संचालन से संबंधित अन्य सहायक खर्चों के लिए विदेशी प्रायोजन से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था। ईडी द्वारा ओएमआईएफ़ इंडिया के कार्यालयों और प्रमुख पदाधिकारियों के आवासों पर की गई तलाशी में संपत्ति के दस्तावेज़, वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज़ब्त किए गए और उनकी जाँच से पता चला कि छात्र प्रायोजन डेटा में जानबूझकर हेराफेरी की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रायोजित बताए गए छात्रों की संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना और अतिरिक्त विदेशी दान प्राप्त करने को उचित ठहराना था।

छात्र डेटा में हेरफेर में एक ही व्यक्ति को कई छात्र कोड देना, अलग-अलग वर्षों के लिए अलग-अलग छात्र कोड, एक ही कोड के तहत अलग-अलग छात्रों को रखना, व्यक्तिगत विवरणों (फोटो, जन्मतिथि और माता-पिता के नाम) में बदलाव करना और ऊंचाई, कक्षा, जाति और लिंग जैसे अन्य मापदंडों में विसंगतियां शामिल थीं। आरोपियों द्वारा डेटा को सीमित रखने का हवाला देते हुए ऐतिहासिक डेटा को छिपाने के प्रयास के बावजूद, जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से पता चला कि ओएमआईएफ ने कई वर्षों तक फैले व्यापक छात्र डेटासेट को संरक्षित रखा था।

ईडी की जांच से यह साबित हुआ है कि गुड शेफर्ड स्कूलों ने सभी छात्रों से नियमित शुल्क, किताबों का शुल्क, यूनिफॉर्म और बस शुल्क वसूला, जिनमें वे छात्र भी शामिल थे जिन्हें पूर्ण रूप से प्रायोजित बताया गया था। इस प्रकार उन्होंने अपराध की आय अर्जित की। स्कूलों को आरटीई और छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत सरकार से पर्याप्त सहायता भी मिली, फिर भी छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया और सरकारी प्रतिपूर्ति छात्रों को वापस करने के बजाय ओएमआईएफ के मुख्यालय के खातों में भेज दी गई। 2011-12 और 2017-18 के बीच, छात्रों से एकत्र की गई और सरकारी स्रोतों से प्राप्त बड़ी रकम को दानदाताओं से छिपाया गया, जो मानते थे कि वे मुफ्त शिक्षा के लिए धन

दे रहे हैं। ईडी ने छात्रों से एकत्र की गई इस तरह की फीस और सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग से प्राप्त 15.37 करोड़ रुपये की अपराध की आय की पहचान की है।

2014-15 और 2016-17 के बीच, ओएमआईएफ द्वारा दर्ज की गई पुस्तकों, वर्दी, टाई, बेल्ट और बस सेवाओं पर होने वाले खर्चों को गुड शेफर्ड कम्युनिटी सोसाइटी (जीएससीएस) को हस्तांतरित कर दिया गया, जो धार्मिक गतिविधियों में संलग्न एक संस्था है। ये राशियाँ सीधे छात्रों और अभिभावकों से एकत्र की गईं और जीएससीएस द्वारा स्थानीय दान के रूप में दर्ज की गईं, जिनका उपयोग बाद में चर्च से संबंधित खर्चों और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि गबन किए गए धन को संबद्ध संस्थाओं के मुख्य कार्यों के लिए भेजा गया और वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा भव्य विदेश यात्राओं पर खर्च किया गया, जिसमें डॉ. जोसेफ डिसूज़ा और अन्य की बिजनेस क्लास यात्राएं शामिल हैं। फर्जी खर्चों को दर्ज करके गबन किए गए धन को नकद में निकाला गया और इसका उपयोग प्रमुख पदाधिकारियों और उनके द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। जांच में पता चला है कि गुड शेफर्ड चर्चों के स्व-घोषित आर्कबिशप डॉ. जोसेफ ग्रेगरी डिसूज़ा सभी समूह संस्थाओं पर आध्यात्मिक, प्रशासनिक और रणनीतिक नियंत्रण रखते थे, जबकि उनके बेटे जोश लॉरेंस डिसूज़ा परिचालन और वित्तीय प्रमुख के रूप में काम करते थे, जो हेरफेर किए गए रिकॉर्ड रखने, विदेशी धन के प्रबंधन, अंतर-संस्था हस्तांतरण के समन्वय और दाताओं के साथ संचार संभालने के लिए जिम्मेदार थे।

यह भी सामने आया है कि डॉ. जोसेफ डिसूज़ा कई विदेशी दान संगठनों के संस्थापक सदस्य थे और भारतीय संस्थाओं के संचालन के लिए धन जुटाने हेतु अक्सर विदेश यात्रा करते थे। विदेशी दान संगठनों की वेबसाइटें भारत से अस्पष्ट या दुर्गम पाई गईं, जिससे नियामक जांच से बचने के लिए जानबूझकर लगाए गए प्रतिबंधों का संकेत मिलता है।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि ओम इंडिया समूह ने विदेशी दानदाताओं से अधिक प्रायोजन राशि प्राप्त करने के लिए गुड शेफर्ड स्कूल की साधारण छात्राओं को *"जोगिनी"* (यौन शोषण का शिकार हुई मंदिर परिचारिकाएँ) के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया। दानदाताओं की वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर नियमित छात्राओं और अन्य बच्चों की तस्वीरें *जोगिनी* के रूप में अपलोड की गईं, जबकि इन बच्चों का ऐसा कोई इतिहास नहीं था और न ही कोई पुनर्वास कार्यक्रम मौजूद था। "जोगिनी पुनर्वास" के लिए दान राशि 60-68 अमेरिकी डॉलर प्रति माह थी, जबकि नियमित छात्रों के प्रायोजन के लिए 20-28 अमेरिकी डॉलर प्रति माह थी, जिसके परिणामस्वरूप गलत प्रस्तुतियों के आधार पर अधिक धन जुटाया गया।

क्षेत्रीय सत्यापन के बाद, गृह मंत्रालय [विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) प्रभाग] ने एफसीआरए, 2010 के उल्लंघन के लिए कई ओएम इंडिया संस्थाओं के एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण रद्द करने का आदेश दिया और उनके एफसीआरए खातों को फ्रीज कर दिया। हालांकि, समूह के नेतृत्व ने विदेशी दानदाताओं के साथ मिलीभगत करके, एफसीआरए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, मुद्रण संबंधी वाणिज्यिक बिलों की आड़ में ओएम बुक्स फाउंडेशन (ओएमबीएफ) के माध्यम से विदेशी धन प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीके अपनाए।

अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि की पहचान और हेराफेरी किए गए धन को लॉन्ड्रिंग करने में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की पहचान सहित आगे की जांच जारी है।